भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1858

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

1858. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री राजेश रंजन:

श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में यथाघोषित कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना तथा बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए बैराज सहित सिंचाई से संबद्ध परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक व्यय की गई निधि संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली अन्य स्रोतों जैसे कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक और बिहार की बैराज, नदी प्रदूषण उपशमन और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य मौजूदा और नई योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की किसी भी योजना के तहत केंद्रीय सहायता पाने वाले सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा तकनीकी जांच और उसके बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अनिवार्य है।

सीडब्ल्यूसी द्वारा कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना की जांच की गई और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा कुल 6,282.32 करोड़ रुपये

की कुल लागत का मूल्यांकन किया गया। इस परियोजना को 3,652.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,143.22 करोड़ रुपये की शेष लागत हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल किया गया था। पूंजी निवेश संबंधी राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के अंतर्गत परियोजना को 631.59 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता भी प्रदान की गई है। इस परियोजना पर अब तक 263.40 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया जा चुका है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 में, 'बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) की 'नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य' (आरएमबीए) योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्त पोषण से एक बाढ़ प्रबंधन परियोजना नमत: बागमती, सीतामढ़ी डिवीज़न के अंतर्गत 13.8035 करोड़ रुपये से जमला-रसूलपुर गांव में 1,314 मीटर की कुल लंबाई में 30 बेड बार और स्लोप पिचिंग का निर्माण, तथा बैरगनिया रिंग बांध (900 मीटर) का निर्माण शामिल किया गया और इस परियोजना के लिए 4.145 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत अन्य सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं तकनीकी जांच/मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) या बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत केंद्रीय सहायता के लिए नई परियोजनाओं को शामिल करने के संबंध में निर्णय 16वें वित्त आयोग की अवधि के समवर्ती वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों और पीएमकेएसवाई/एफएमबीएपी के लिए वित्तीय आवंटन पर निर्भर करता है।

*****